मुम्मारेड्डी नागी रेड्डी और अन्य

बनाम

पिट्टी दुरईराजा नायडू और अन्य

(मेहर चंद महाजन, मुखर्जी और विवियन बोस जेजे.)

हिंदू कानून-विधवा-आत्मसमर्पण-बेटी और दामाद के पक्ष में त्याग-वैधता- प्रत्यावर्ती द्वारा वाद- अन्तर्वती लाभ का अधिकार।

जहां एक हिंदू विधवा, जिसे अपने पति की संपत्ति विरासत में मिली थी, ने अपनी बेटी जो अगली प्रत्यावर्तक थी और बेटी के पति के पक्ष में संयुक्त रूप से एक विलेख निष्पादित किया, जिसे मुक्ति/त्याग विलेख के रूप में वर्णित किया गया है।

यह माना गया कि हालांकि हिंदू कानून के तहत एक विधवा के लिए यह खुला है कि वह अपनी संपत्ति को अगले उत्तराधिकारी को सौंप दे, भले ही वह एक महिला उत्तराधिकारी हो, एक विधवा वैध रूप से अगली महिला उत्तराधिकारी और किसी अजनबी के पक्ष में संयुक्त रूप से आत्मसमर्पण नहीं कर सकती है। इस तरह के लेन-देन को महिला उत्तराधिकारी के पक्ष में समर्पण और उसके द्वारा अजनबी को हस्तांतरण के रूप में नहीं माना जा सकता है, और यह अंतिम प्रत्यावर्तियों पर बाध्यकारी नहीं है।

जगरानी बनाम गया (ए.आई.आर. 1933 इलाहबाद 856) स्वीकृत। नोबो किशोर बनाम. हरिनाथ (आई.एल.आर. 10 कलकत्ता 1102) ने टिप्पणी की। विटला सीतान्ना बनाम मारिवदा (एल.आर. 51 एल.ए. 200), रंगासामी गौंडन बनाम नचियप्पा गौंडन (41 आई.ए. 72) और देवी प्रोसाद बनाम गोला भगत (आई.एल.आर. 40 ब्स. 721) का उल्लेख है।

एक हिंदू विधवा द्वारा किए गए वयन/अंतरण को रद्द करने के लिए प्रत्यावर्तनकर्ता/प्रत्यावर्तिकर्ता द्वारा किए गए मुकदमें में विधवा की मृत्यु की तारीख से पुनर्वित्तकर्ता को लाभ दिया जा सकता है, भले ही ऐसा अंतरण शून्य न हो।

यहां तक कि ऐसे मामलों में जहां प्रत्यावर्तिकर्ता के पक्ष में कब्जे की डिक्री इस बात पर सशर्त है कि वह, वह राशि जमा करेगा जिसका उपयोग संपत्ति के लाभ के लिए किया गया है, यदि उसे अंतरण पर ब्याज का भुगतान करने का आदेश दिया जाता है तो अन्तःकालीन लाभ प्रत्यावर्तिकर्ता को दिया जा सकता है।

भगवत दयाल बनाम देवी दयाल (एल0आर0 35 आई-ए-48) एवं सतगुर प्रसाद बनाम हरिनारायण सिंह (एल0आर0 59 एल-ए-147) का उल्लेख किया गया है। बनवारीलाल बनाम महेश (आई0एल0आर0 41 इलाहबाद 63) विशिष्ट।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार 1950 की सिविल अपील संख्या 51

मद्रास उच्च न्यायालय के 12 जनवरी, 1948 के फैसले और डिक्री के खिलाफ अपील (सी.जे. और सत्यनारायण राव जे.)

नेल्लोर के अधीनस्थ न्यायाधीश की 1940 की ओ.एस. सं0-3 में पारित डिक्री दिनांकित 17 अगस्त, 1942 से उत्पन्न 1945 की अपील संख्या 167

अपीलकर्ताओं के लिए के. राजा अय्यर (आर. गणपति अय्यर, उनके साथ)

उत्तरदाताओं/प्रत्यर्थियों के लिए बी. सोमैया (एम. कृष्णा राव, उनके साथ)

1951. 8 मई. न्यायालय का निर्णय निम्न के द्वारा सुनाया गया।

मुखर्जी जे.-यह अपील 12 जनवरी, 1948 को मद्रास उच्च न्यायालय की एक खण्डपीठ के अपीलीय फैसले के खिलाफ निर्देशित है, जिसमें 1940 के ओ.एस. नंबर 3 में नेल्लोर के अधीनस्थ न्यायाधीश के फैसले को आंशिक रूप से उलट दिया गया था।

मामले के भौतिक तथ्यों और पक्षों के बीच केंद्र में उत्पन्न विवाद का विश्लेषण करने के लिए, एक संक्षिप्त वंशावली का उल्लेख करना सुविधाजनक होगा जो नीचे दी गई हैः-

उदथ नारायणप्पा चंचम्मा (मृत्यु 1933)

वेंकट नरसम्मा (मृत्यु 1926)

पिट्टी रंगय्या (मृत्यु 1914)

वेंकटाद्रि-राजकंठम्मा

दुरईराजा	राजवती	बालाकृष्णा	कृष्णाबाबूलू
वादी-1	वादी-2	वादी-3	वादी-4

विवादित संपत्तियाँ जो वादी की अनुसूची-ए में वर्णित हैं, स्वीकार्य रूप से नारायणप्पा की थी जो वादी की दादी के पिता थे। 1884 से कुछ समय पहले नारायणप्पा की बिना वसीयत मृत्यु हो गई, जिससे उनकी पत्नी चंचम्मा और वेंकट नरसम्मा नामक एक बेटी जीवित रहीं। नरसम्मा की शादी पिट्टी रंगय्या से हुई थी और उनका वेंकटाद्रि नाम का एक बेटा था, जो वादी का पिता था। चंचम्मा की मार्च, 1933 में मृत्यु हो गई, और वादी का कहना है कि वे नारायणप्पा की बेटी के बेटे के बेटे के रूप में उनके पैतृक बंधु थे और अस्तित्व में कोई करीबी उत्तराधिकारी नहीं होने के कारण, वे नारायणप्पा की मृत्यु पर छोड़ी गई सभी संपत्तियों के हकदार बन गए। ऐसा प्रतीत होता है कि 22 फरवरी, 1894 को चंचम्मा ने अपनी बेटी नरसम्मा और अपने दामाद पिट्टी रंगय्या के पक्ष में जिसे त्याग के विलेख के रूप में वर्णित किया गया है, निष्पादित किया, जिसके तहत बाद में नारायणप्पा की पूरी संपत्ति उनके कब्जे में आ गई। इस दस्तावेज के

निष्पादन के बाद चंचम्मा की बेटी और दामाद ने नारायणप्पा द्वारा छोड़ी गई संपत्तियों को अपना मानकर अंतरण करना शुरू कर दिया और उस स्तर पर विभिन्न लेनदेन किये। 1914 में पिट्टी रंगय्या की मृत्यु हो गई और नरसम्मा 1926 में उनके पीछे चल बसी। वादपत्र की अनुसूची ए में संपत्ति की छह वस्तुएं शामिल हैं। इन वस्तुओं में से 4 और 5 को वेंकट नरसम्मा ने अपने बेटे, वादी के पिता के साथ, 9 जुलाई, 1922 को 5वें प्रतिवादी और प्रतिवादी 6 से 9 के पिता को 6,500/-रूपये राशि में बेच दिया था। फिर 26 अक्टूबर, 1929 को जब नरसम्मा और वादी के पिता दोनों मर गए तो अनुसूची ए के आइटम 1 को वादी की मां ने उनके संरक्षक के रूप में प्रथम प्रतिवादी को 33,000/-रुपये प्रतिफल के लिए बेच दिया था। प्रतिवादी 2 और 3 प्रथम प्रतिवादी के अविभाजित पुत्र हैं। मुकदमे में अन्य प्रतिवादियों के पक्ष में अन्य हस्तांतरण भी हैं लेकिन वे हमारे समक्ष अपील की विषय-वस्तु नहीं हैं।

वादी के आरोप वास्तव में यह हैं कि ये अंतरण उन पर बाध्यकारी नहीं हैं क्योंकि विधवा द्वारा निष्पादित तथाकथित त्याग का विलेख समर्पण के विलेख के रूप में काम नहीं कर सकता था और इस विलेख के आधार पर कोई भी हस्तांतरण नहीं किया जा सकता था। वेंकट नरसम्मा या उनके बेटे, वेंकटाद्रि द्वारा या यहां तक कि वादी की ओर से उनकी मां द्वारा अभिभावक के रूप में विधवा की मृत्यु के बाद अधिकार नहीं हो सकते थे। चूँकि ये हस्तांतरण चंचम्मा के जीवनकाल के दौरान और बिना

किसी कानूनी आवश्यकता के किए गए थे, वास्तविक प्रतिवर्ती के रूप में वादी उनसे बाध्य नहीं थे और वे हस्तांतरित अन्तरितियों को बेदखल करके संपत्तियों पर कब्जा पाने के हकदार हैं। इन संपत्तियों पर कब्जा वापस पाने के लिए ही वर्तमान मुकदमा लाया गया था और साथ ही विधवा की मृत्यु की तारीख से कब्जा देने की तारीख तक अन्तःकालीन लाभ का भी दावा किया गया था।

ऊपर उल्लिखित संपत्तियों में हित रखने वाले प्रतिवादियों का बचाव वास्तव में तीन रूपों में था। पहले स्थान पर यह तर्क दिया गया था कि वादी नारायणप्पा के अगले प्रत्यावर्ती उत्तराधिकारी नहीं थे और परिणामस्वरूप विधवा की मृत्यु पर नारायणप्पा की संपत्ति पर उत्तराधिकार पाने के हकदार नहीं थे। दूसरा तर्क यह था कि त्याग विलेख विधवा की संपत्ति को बेटी के पक्ष में समर्पण के रूप में संचालित होता था, जो अगली प्रत्यावर्तक थी और हालांकि इस तरह के समर्पण से बेटी को केवल एक सीमित संपत्ति ही मिल सकती थी, जिसकी वह हकदार होती। विधवा की मृत्यु फिर भी चूँकि 1926 में बेटी की मृत्यु हो गई, वर्तमान मुकदमा जो मृत्यु की तारीख के 12 साल से अधिक समय बाद स्थापित किया गया था, परिसीमा द्वारा वर्जित कर दिया गया था। तीसरी दलील यह थी कि किसी भी स्थिति में इन अंतरणों को खारिज नहीं किया जा सकता क्योंकि वे कानूनी आवश्यकता द्वारा उचित थे।

मुकदमे की सुनवाई करने वाले विद्वान अधीनस्थ न्यायाधीश ने वादी पक्ष के प्रतिकूल निर्णय दिया। सबसे पहले यह माना गया कि यद्यपि वादी नारायणप्पा के वंशानुगत बंधु थे, लेकिन उनके द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य यह स्थापित करने में विफल रहे कि अस्तित्व में कोई अज्ञेय संबंध या करीबी उत्तराधिकारी नहीं थे। जहां तक विधवा द्वारा अपनी बेटी और दामाद के पक्ष में निष्पादित त्याग के दस्तावेज (प्रदर्शन पी. 6) का संबंध है, अधीनस्थ न्यायाधीश इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि यह विलेख विधवा की संपत्ति के समर्पण के रूप में था। बेटी की मृत्यु 1926 में हो गई, वादी का मुकदमा परिसीमा द्वारा वर्जित कर दिया गया। कानूनी आवश्यकता के प्रश्न पर अधीनस्थ न्यायाधीश द्वारा दर्ज निष्कर्ष यह था, कि प्रथम प्रतिवादी के पक्ष में निष्पादित बिक्री विलेख (प्रदर्शनी डी-1) 5,061/- रुपये और विषम आने की सीमा तक कानूनी आवश्यकता द्वारा समर्थित था और वह अन्य दस्तावेज जिसके तहत प्रतिवादियों 5 से 9 ने स्वामित्व का दावा किया था, संपत्ति पर बिल्कुल भी बाध्यकारी नहीं था। परिणामस्वरूप, वादी का मुकदमा पूरी तरह से खारिज कर दिया गया।

इस फैसले के खिलाफ वादी ने मद्रास उच्च न्यायालय में अपील की और अपील की सुनवाई जेंटल सीजे और सत्यनारायण राव जे की खंडपीठ ने की। विद्वान न्यायाधीशों ने ऊपर उल्लिखित संपत्ति की वस्तुओं के संबंध में अपील की अनुमति दी और ट्रायल जज के फैसले को उस हद तक पलट दिया। यह माना गया कि वादी नारायणप्पा के निकटतम

प्रत्यावर्ती उत्तराधिकारी थे और त्याग विलेख विधवा की संपत्ति के समर्पण के रूप में काम नहीं करता था। वादी को अदालत में 5,061/-रूपये और कुछ आने की राशि जमा करने की शर्त पर प्रतिवादी 2 और 3 के मुकाबले अनुसूची संपत्तियों के आइटम 1 के संबंध में कब्जे के लिए एक डिक्री दी गई थी। यह संपत्ति पर कानूनी रूप से बाध्यकारी ऋण की राशि थी जिसे हस्तांतरण की बिक्री आय से मुक्त कर दिया गया था और इस राशि पर छह प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भुगतान कुछ निर्दिष्ट तिथियों से जमा करने की तिथि तक करने का एक और निर्देश था। यहां यह ध्यान दिया जा सकता है कि ट्रायल कोर्ट के फैसले के बाद पहले प्रतिवादी की मृत्यु हो गई और उसका हित प्रतिवादी 2 और 3 के उत्तरजीवी जो उसके अविभाजित पुत्र हैं, को दे दिया गया। प्रतिवादी 5 से 9 के विरुद्ध अनुसूची ए के आइटम 4 और 5 के संबंध में कब्जे की वसूली के लिए बिना शर्त डिक्री थी। वादी को विधवा की मृत्यु की तारीख से और भविष्य में कब्जे की तारीख तक दोनों के लिए अंतःकालीन लाभ हेतु एक डिक्री दी गई थी और अंतःकालीन लाभ की राशि को सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 20 नियम 12 के तहत एक अलग कार्यवाही में सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया था। इस निर्णय के विरुद्ध वर्तमान अपील प्रतिवादी 2, 3 और 5 से 9 द्वारा प्रस्तुत की गई है।

अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित श्री राजा अय्यर ने उच्च न्यायालय के इस निष्कर्ष को गंभीरता से चुनौती नहीं दी कि चंचम्मा की

मृत्यु के समय वादी ही निकटतम प्रतिवादी थे। उन्होंने दो बिंदुओं पर उच्च न्यायालय के फैसले के औचित्य पर चुनौती दी। उनका पहला तर्क यह है कि चंचम्मा द्वारा निष्पादित त्याग विलेख (प्रदर्शनी पी-6) में विधवा की संपत्ति को उसकी बेटी और दामाद के पक्ष में समर्पण करने का प्रभाव था और वादी की बेटी की 1926 में मृत्यु हो गई थी। मुकदमा परिसीमा द्वारा वर्जित था। दूसरा तर्क यह दिया गया है कि उच्च न्यायालय को वादी को विधवा की मृत्यु की तारीख से व्यक्तिगत लाभ की डिक्री नहीं देनी चाहिए थी। अंतःकालीन लाभ अधिकतम रूप से वाद संस्थित किये जाने की दिनांक से दिलाया जा सकता था और जहां तक प्रतिवादी 2 और 3 का संबंध है, जिनके खिलाफ एक सशर्त डिक्री दी गई थी। अंतःकालीन लाभ को केवल उस समय से अनुमति दी जा सकती थी जब वादीगण द्वारा न्यायालय में निर्दिष्ट धनराशि जमा कराने की शर्त पूरी कर दी जाये।

अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील द्वारा लिया गया पहला बिंदु दस्तावेज (प्रदर्श पी-6) जिस पर प्रतिवादी मुख्य रूप से अपने तर्क को आधार बनाते हैं, के कानूनी प्रभाव पर सवाल उठाता है। दस्तावेज 50 वर्ष से अधिक पुराना है और इसकी भाषा बहुत स्पष्ट या निश्चित नहीं है। यह, यह कहते हुए शुरू और समाप्त होता है कि यह त्याग का एक विलेख है। इसमें कहा गया है कि चूँकि निष्पादक एक महिला है जो अपने सांसारिक मामलों की देखभाल करने में असमर्थ है और क्योंकि जिन व्यक्तियों के पक्ष में दस्तावेज निष्पादित किया गया है, वे निष्पादक के दामाद और बेटी

हैं, उसने अपनी सारी चल व अचल संपत्तियां उनके कब्जे में दे दी है। फिर संपत्तियों का विवरण आता है और उसके बाद प्रावधान लागू होते हैं:-

"इसलिए आप स्वयं सरकार को हर साल देय किराया आदि का भुगतान करेंगे और अपने बेटे से लेकर पोते तक और इसी तरह वंशानुगत रूप से स्थायी रूप से इसका आनंद लेंगे। मेरे जीवनकाल के लिए आप हमारे रखरखाव के खर्च के लिए 360 रुपये प्रति वर्ष फाल्गुन महीने से पहले भुगतान करेंगे।"

विलेख के शेष भाग उसके प्राप्तकर्ताओं को अन्य लोगों द्वारा निष्पादक को देय सभी ऋणों की वसूली करने और उसके द्वारा देय सभी उचित ऋणों का भुगतान करने का कर्तव्य अधिरोपित करते हैं। अंत में यह कहा गया है कि भूमि एक नरसिम्हा नायडू के पक्ष में विधवा द्वारा निष्पादित इजारा पट्टे के तहत है जो 1346 फसली के अंत तक समाप्त होने वाली है और यह बेटी और दामाद के द्वारा तय किया जायेगा कि वे पट्टे के संबंध में क्या करेंगे।

विलेख में हस्तांतरण शब्द का उपयोग नहीं किया गया है, हालांकि विधवा अपने दामाद और बेटी को संपत्ति में उपयोग उपभोग के वंशानुगत अधिकार प्रदान करने का इरादा रखती है। दस्तावेज को एक विज्ञप्ति के रूप में वर्णित किया गया है और इस पर मुहर भी लगाई गई है। जाहिर तौर पर इसमें वे सभी संपत्तियां शामिल हैं जो विधवा के पास थी और एक

तरह से दस्तावेज महिला की ओर से व्यावसायिक मामलों से सभी संबंध छोड़ने के इरादे को इंगित करता है। प्रथम दृष्टया ये तथ्य समर्पण की कहानी को बल देते हैं। इस बात पर विवाद नहीं है और न ही इस पर विवाद किया जा सकता है, कि समर्पण तब भी हो सकता है, जब अगली प्रत्यावर्ती महिला स्वयं उत्तराधिकारी हो, जो संपत्ति में सीमित हित रखती हो। हालांकि इस तरह के समर्पण से उसे उत्तराधिकार कानून के तहत उत्तराधिकारी के रूप में मिलने वाले हित से अधिक हित नहीं मिल सकता है। हालाँकि इस मामले में पूरी कठिनाई इस तथ्य से पैदा हुई है, कि विधवा अपने पति की संपत्ति को दो व्यक्तियों के पक्ष में छोड़ने के अपने अधिकार का प्रयोग करना चाहती है, जिनमें से एक अगला उत्तराधिकारी है, लेकिन दूसरा हालांकि उससे संबंधित है जो उसका दामाद है। जहां तक विरासत के अधिकारों का सवाल है, दामाद के रूप में वह पूरी तरह अजनबी है और इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि उसका इरादा था कि उसके पति की संपत्ति उसकी अपनी बेटी के साथ संयुक्त रूप से दामाद को मिले।

विधवा द्वारा पति की संपत्ति में अपने हित के समर्पण या परित्याग का सिद्धांत जिसका प्रभाव उसके पति के अगले उत्तराधिकारी के पक्ष में विरासत को गति देने में होता है, अब हिंदू कानून का एक सुस्थापित सिद्धांत है जिसे न्यायिक निर्णयों की एक लंबी श्रृंखला द्वारा स्थापित किया गया है। हालाँकि न्यायिक घोषणाओं को पूरी तरह से एक समान या

सुसंगत नहीं कहा जा सकता है, फिर भी उस मूल सिद्धांत के संबंध में कोई संदेह नहीं हो सकता है जिस पर सिद्धांत आधारित है, अर्थात यह विधवा द्वारा आत्मदाह या उसकी जीवन संपत्ति की वापसी है जो उस तिथि पर मृत पति की संपत्ति उसके अगले उत्तराधिकारियों के लिए खोल देता है। ''यह याद रखना चाहिए'' इस प्रकार विटला सीतान्ना बनाम मारिवाड़ा एलआर 61 आईए 200/207 में न्यायिक समिति ने कहा "सिद्धांत का आधार विधवा का विनाश है" संपत्ति और न कि पूर्व दृष्टया हस्तांतरण जिसके द्वारा ऐसा विनाश किया जाता है। इसका परिणाम केवल यह होता है, कि पति विधवा के स्थान पर अगले उत्तराधिकारी के रूप में कदम रखता है। यह विनाश किसी भी प्रक्रिया द्वारा किया जा सकता है और यह आवश्यक नहीं है कि किसी विशेष रूप का प्रयोग किया जाए। बस इतना आवश्यक है कि संपत्ति रखने के लिए विधवा के अधिकार का वास्तविक और पूर्ण त्याग होना चाहिए और समर्पण केवल संपत्ति को उलटने वालों के साथ विभाजित करने का एक उपकरण नहीं होना चाहिए। रंगासामी गौंडन बनाम नाचियप्पा गौंडन एलआर 41 आईए के अनुसार 72 । समर्पण के सिद्धांत में अंतर्निहित सिद्धांत से यह स्पष्ट है कि पति के अगले उत्तराधिकारी को छोड़कर किसी के पक्ष में कोई भी समर्पण और संपत्ति का परिणामी अंतरण संभवतः नहीं किया जा सकता है। यह सच है कि संपत्ति को उसके पास निहित करने के लिए पुनर्विक्रेता की ओर से कोई स्वीकृति या सहमति का कार्य आवश्यक नहीं है, निहितीकरण कानून के

तहत होता है। लेकिन विधवा के लिए यह कहना संभव नहीं है कि वह अपने पति की संपत्ति से खुद को अलग कर रही है ताकि वह पति के अगले उत्तराधिकारी के अलावा किसी और के पास जा सके। अजनबी के पक्ष में स्थानांतरण का कार्य हो सकता है, त्याग का नहीं। यदि जैसा कि वर्तमान मामले में हुआ है, स्थिति में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं होता है, समर्पण अगले उत्तराधिकारी के पक्ष में किया जाता है जिसके साथ कोई अजनबी जुड़ा हुआ है और विधवा संपत्ति को त्यागने का इरादा रखती है ताकि यह उन दोनों में निहित हो सके। जहां तक अगले उत्तराधिकारी का सवाल है, ऐसे मामले में विधवा के संपूर्ण हित का समर्पण नहीं हो सकता, क्योंकि वह वास्तव में निर्देश देती है कि इसका एक हिस्सा पति के उत्तराधिकारी के अलावा किसी और के पास होना चाहिए या उसका उपयोग उपभोग लिया जाना चाहिए। जहाँ तक अजनबी का प्रश्न है, त्याग का प्रश्न ही नहीं हो सकता। लेन-देन अधिक से अधिक उसको उपहार देने के इरादे का साक्ष्य हो सकता है, हालांकि ऐसा इरादा उचित कानूनी रूप में नहीं हो सकता है। श्री राजा अय्यर ने हमें यह मानने के लिए प्रेरित करने का एक परजोर प्रयास किया कि दस्तावेज वास्तव में दो अलग-अलग लेनदेन को मिलाकर एक समग्र दस्तावेज है, एक-विधवा द्वारा अपनी बेटी के पक्ष में पूरी संपत्ति के समर्पण का कार्य और दूसरा, इस प्रकार बेटी में निहित हित के एक हिस्से का उसके पति के पक्ष में हस्तांतरण। यदि दस्तावेज को इस तरह से पढ़ा और व्याख्या किया जा सकता है, तो जाहिर तौर पर निर्णय

अपीलकर्ताओं के पक्ष में होना चाहिए, लेकिन हमारी राय में दस्तावेज की व्याख्या करने के तरीके में कठिनाइयाँ और अविश्वसनीय प्रकृति की प्रतीत होती हैं। दस्तावेज न तो किसी रूप में और न ही सार में बेटी के पक्ष में ही केवल विधवा की पूरी संपत्ति के त्याग का संकेत देता है, न ही इस बात का कोई संकेत है कि दामाद को दिया जाने वाला हित उसे प्राप्त हो रहा था। बेटी से स्थानांतरण के माध्यम से यह दस्तावेज विधवा और उसकी बेटी द्वारा संयुक्त रूप से दामाद के पक्ष में निष्पादित नहीं किया गया है, जिसमें विधवा द्वारा बेटी के पक्ष में संपत्ति का त्याग करने और उसी का एक हिस्सा दामाद को हस्तांतरित करने का उल्लेख शामिल है। बेटी को न तो विलेख के निष्पादक के रूप में और न ही प्रमाणित गवाह के रूप में दर्शाया गया है। वह अपने पति के साथ विलेख की प्राप्तकर्ता है और दस्तावेज से यह बताना असंभव है कि या तो उसे अपनी मां द्वारा त्यागने पर पूरी संपत्ति प्राप्त हुई या उसे स्थानांतरित कर दिया गया या यहां तक कि इसका एक हिस्सा अपने पति को हस्तांतरित करने की सहमति दी गई।

इस विवाद के समर्थन में श्री अय्यर ने नोबोकिशोर बनाम हरिनाथ में कलकत्ता उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के फैसले में प्रतिपादित सिद्धांत पर बहुत भरोसा किया, जिसे रंगास्वामी गौंडन बनाम नचिअप्पा गौंडन एलआर 46 आईए 72 में न्यायिक समिति द्वारा निहित रूप से स्वीकार कर लिया गया था। इसे कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा कई मामलों में

उल्लेख किया गया था, जिनकी नोबोकिशोर बनाम हरिनाथ आईएलआर 10 कलकत्ता में समीक्षा की गई और पुष्टि की गई, कि एक विधवा अपने पति की पूरी संपत्ति को बिना किसी आवश्यकता के लेकिन अगले प्रत्यावर्तक की सहमति से बेचने या हस्तांतरित करने की हकदार है, ताकि उसकी मृत्यु के समय वास्तविक प्रत्यावर्तक के अधिकारों पर रोक लगाई जा सके। इसे न्यायिक समिति ने रंगासामी गौंडन बनाम नचिअप्पा गौंडन आईएलआर 46 आईए 72 में समर्पण के सिद्धांत के विस्तार के रूप में समझाया था। "समर्पण एक बार किया गया", उनके आधिपत्य को देखते हुए, "निकटतम प्रत्यावर्ती या प्रत्यावर्तक के पक्ष में, संपत्ति उसकी या उनकी हो गई, और यह सिद्धांत का एक स्पष्ट विस्तार था कि यद्यपि वह या वे किसी तीसरे पक्ष को संपत्ति हस्तांतरित करने के हकदार थे, यह वही बात थी यदि संपत्ति विधवा द्वारा उसके या उसके साथ की गई थी उनकी सहमति। नोबोकिशोर के मामले द्वारा यह संभव होना तय किया गया था। निर्णय समर्पण के सिद्धांत पर चला गया, और यह पूरी संपत्ति के समर्पण के लिए ऐसा कर सकता है, लेकिन यह ध्यान देने योग्य है कि संदर्भ के आदेश से पता चलता है कि अंतरण स्पष्ट रूप से आवश्यकता के आधार पर था, इसलिए ऊपर दिए गए दूसरे शीर्षक के तहत उल्लिखित आधारों पर इसका समर्थन किया जा सकता था।"

यह कानून के स्थापित सिद्धांतों के साथ काफी सुसंगत होगा कि यदि विधवा पति की संपत्ति में अपना हित छोड़ देती है और प्रत्यावर्तक

जिसके पास संपत्ति निहित है वह संपत्ति को पूरी तरह से या आंशिक रूप से किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित कर देता है। यदि हस्तांतरण पूरी संपत्ति का है, तो दोनों लेन-देन को एक दस्तावेज में जोड़ा जा सकता है और विधवा और प्रत्यावर्तनकर्ता संयुक्त रूप से पूरी संपत्ति को किसी अजनबी को हस्तांतरित कर सकते हैं, लेकिन ऐसे मामलों में निहितार्थ हमेशा यह होना चाहिए कि अन्तरिति व्यक्ति को प्रत्यावर्ती से अपना अधिकार प्राप्त होता है, विधवा से नहीं। नोबोकिशोर बनाम हरिनाथ (2) के मामलों के वर्ग में इस सिद्धांत का विस्तार दूर की कौडी और कुछ हद तक विसंगतीपूर्ण प्रतीत होता है। इन मामलों में विधवा द्वारा अजनबी को पूरी संपत्ति हस्तांतरित करने के लिए तत्काल प्रत्यावर्तक की सहमति देने के प्रभाव को एक दोहरी कल्पना के रूप में माना गया है, पहला विधवा द्वारा सहमति देने वाले प्रत्यावर्ती के पक्ष में समर्पण की कल्पना है और दूसरा, अन्तरिति/ग्रहण करने वाले द्वारा दूसरे व्यक्ति को स्थानांतरण की कल्पना है। हालांकि दोनों कल्पनाएं वास्तविक तथ्यों के विपरीत हैं। सबसे पहले यह कहना मुश्किल है कि जब विधवा संपत्ति सीधे अजनबी को देती है, न कि प्रत्यावर्ती वाले को तो समर्पण क्यों माना जाना चाहिए। यदि इस स्थिति को मान भी लिया जाए तब भी यह प्रश्न उठता है कि किसी पक्ष की सहमति किसी हस्तांतरण की जगह कैसे ले सकती है, जो हस्तांतरिती में स्वामित्व निहित करने के उद्देश्य से अपेक्षित है। एक सहमति केवल सहमति देने वाले पक्ष या किसी अन्य व्यक्ति को जो उससे अपना शीर्षक

प्राप्त करता है, को बाध्य करती है। यदि विधवा की मृत्यु की तिथि पर वास्तविक प्रत्यावर्तनकर्ता वही व्यक्ति है जिसने अपनी सहमति दी थी, तो जाहिर तौर पर उसे स्थानांतरण को चुनौती देने से रोका जा सकता है, लेकिन वास्तविक प्रत्यावर्तनकर्ता एक अलग व्यक्ति है। यह मानने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है, कि वह उस व्यक्ति द्वारा व्यक्त की गई सहमति से बाध्य होगा जिसके पास उस समय उत्तराधिकार की संभावना के अलावा कुछ भी नहीं था। (अली मोहम्मद बनाम एमएसटी नुघलानी एआईआर 1946 इलाहबाद 180 में महाजन जे. की टिप्पणियाँ देखें) सर रिचर्ड गर्थ सीजे ने नोबोकिशोर बनाम हरिनाथ आईएलआर 10 कलकत्ता, 1102 में अपने फैसले में उस दृष्टिकोण की औचित्यता पर काफी संदेह व्यक्त किया कि विधवा द्वारा उसके प्रत्यावर्तक की सहमति से बिक्री करना वास्तविक त्याग के समान स्तर पर है। लेकिन अदालत के पिछले निर्णयों की एक श्रृंखला के मद्देनजर वह उस दृष्टिकोण को सही मानने के लिए बाध्य थे।

इस विषय पर संपूर्ण कानून पर कभी न कभी इस न्यायालय को पुनर्विचार करना आवश्यक हो सकता है। ऐसा संभव प्रतीत होता है कि प्रिवी काउंसिल ने नोबोकिशोर के मामले में निर्णय को समर्पण के सिद्धांत के दृष्टिकोण से आलोचनात्मक परीक्षण के अधीन नहीं किया, क्योंकि उस मामले में अंतरण को कानूनी आवश्यकता के आधार पर भी बरकरार रखा गया था। वर्तमान मामले के प्रयोजन के लिए हम इस धारणा पर आगे

बढ़ेंगे कि नोबोकिशोर के मामले में निर्धारित कानून सही है। जैसा कि सर लॉरेंस जेनकिंस ने सहर्ष व्यक्त किया था, नोबोकिशोर के मामले में निर्णय की राह कठिनाइयों से रहित नहीं थी, लेकिन विद्वान न्यायाधीशों ने महसूस किया कि यह तय करना होगा कि उपाधियाँ छोड़ी जा सकती हैं। लेकिन यह तय हो गया है कि इसमें कोई सीमा नहीं होनी चाहिए यह बंगाल सिद्धांत देवी प्रसाद बनाम गोला भगत आईएलआर 40 कलकत्ता में प्रति जेनकिंस सी.जे. 721 ।

वर्तमान मामला स्पष्ट रूप से नोबोकिशोर बनाम हरिनाथ में निर्धारित सिद्धांत के दायरे में नहीं आता है, जो किसी अजनबी के पक्ष में संपूर्ण संपत्ति के अंतरण की परिकल्पना करता है, जिसका तत्काल प्रत्यावर्तक सहमति देने वाला पक्ष था। यहां यह नहीं कहा जा सकता कि विधवा के दामाद को पूरा हित उसकी बेटी की सहमति से हस्तांतरित किया गया था। हस्तांतरित हित विधवा द्वारा रखे गए हित का एक अंश था और सख्ती से कहें तो बेटी द्वारा कोई सहमति व्यक्त नहीं की गई थी। वह एक तरह से अपने पति के साथ सहधारक थी। श्री अय्यर का तर्क है कि उनकी सहमति विलेख को स्वीकार करने और उसके आधार पर कई बाद के लेनदेन में शामिल होने से निहित थी, और एक बार यह सहमति स्थापित हो जाने पर हम पूरी संपत्ति के पक्ष में समर्पण की कल्पना उपधारित कर सकते हैं। यह नोबोकिशोर के मामले में सिद्धांत का केवल एक तार्किक विस्तार होगा कि अजनबी के पक्ष में एक आंशिक हस्तांतरण

को भी समर्पण के सिद्धांत पर मान्य किया जा सकता है। हम तर्क की इस शृंखला को सही मानने में असमर्थ हैं। जैसा कि ऊपर कहा गया है, नोबोकिशोर के मामले में सिद्धांत का विस्तार करना सबसे अनुचित होगा जो स्वयं श्री अय्यर के अनुसार ठोस कानूनी सिद्धांतों पर आधारित नहीं है, यह तार्किक परिणाम है। हम इस तरह के मामले में समर्पण की कल्पना का सहारा नहीं ले सकते जब त्याग यदि कोई हो, संपत्ति के एक हिस्से का था और समर्पण के सिद्धांत के आधार पर किसी अजनबी के पक्ष में विधवा द्वारा आंशिक अंतरण को मान्य करने का प्रयास, सिर्फ इसलिए कि प्रत्यावर्ती ने इसके लिए निहित सहमति दी है, हमारी राय में बिल्कुल अनुचित है।

कलकत्ता और बॉम्बे उच्च न्यायालयों के कुछ निर्णयों पर ध्यान देना बाकी है जिन पर श्री राजा अय्यर अपने तर्क के समर्थन में भरोसा करते हैं। अभय पाधा बनाम रामकिंकर का मामला एआईआर 1926 कलकत्ता 228, कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ द्वारा वर्तमान मामले के तथ्यों के समान ही तय किया गया प्रतीत होता है, और प्रथम दृष्टया यह अपीलकर्ताओं के पक्ष में है। वहां एक हिंदू विधवा ने अपने पति के भाई के पक्ष में एक नदबी पत्र या त्याग का विलेख निष्पादित किया, जो निकटतम प्रत्यावर्ती को था और उसके पति के पूर्व मृत भाई के तीन बेटे थे। विधवा की मृत्यु के बाद पति के भाई ने विधवा द्वारा निष्पादित विलेख के तहत अपने भतीजों के अधिकारों से इनकार करते हुए पूरी संपत्ति पर कब्जा

करने का मुकदमा दायर किया। मुकदमा निचली दोनों अदालतों द्वारा खारिज कर दिया गया था और उच्च न्यायालय द्वारा दूसरी अपील में इस निर्णय की पुष्टि की गई थी। उच्च न्यायालय के समक्ष यह मुद्दा निश्चित रूप से उठाया गया था कि लेनदेन को समर्पण के आधार पर बरकरार नहीं रखा जा सकता क्योंकि यह आंशिक रूप से अगले उत्तराधिकारी के पक्ष में समर्पण था और आंशिक रूप से कुछ दूर के उत्तराधिकारियों के पक्ष में अंतरण था। इस बिंदु का निस्तारण कमिंग जे. द्वारा किया गया, जिन्होंने निम्नलिखित तरीके से निर्णय सुनाया:-

> "मुझे नहीं लगता कि इस विवाद में बहुत अधिक सार है। यह सार से अधिक रूप का प्रश्न है। यदि विधवा ने पूरी संपत्ति प्रत्यावर्तक को सौंप दी थी और प्रत्यावर्तक ने उसी क्षण अपनी संपत्ति का अंतरण कर दिया था, उनके भतीजों को लेन-देन के विरुद्ध कुछ भी नहीं कहा जा सकता था और वास्तव में वर्तमान दस्तावेज द्वारा यही किया गया है।"

हमें नहीं पता कि मामले में दस्तावेज की सामग्री वास्तव में क्या थी, न ही पति का भाई दस्तावेज के निष्पादन में शामिल हुआ था या नहीं। चाहे जो भी हो, हम पहले से ही चर्चा किए गए कारणों से इस विचार को स्वीकार नहीं कर सकते हैं कि एक विधवा द्वारा अपनी पूरी संपत्ति को

निकटतम प्रत्यावर्तनकर्ता और एक बाहरी व्यक्ति के पक्ष में संयुक्त रूप से किया गया हस्तांतरण पूरी संपत्ति को तत्काल प्रत्यावर्तनकर्ता को समर्पण के रूप में कार्य करेगा। निःसंदेह यह विबंधन के किसी भी नियम के अधीन है, जिसमें उचित सामग्री के आधार पर प्रकल्पित प्रत्यावर्तक के विरुद्ध आग्रह किया जा सकता है। यह बिल्कुल वही दृष्टिकोण है जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने माउंट जकरानी और अन्य बनाम गया मामले में लिया है, और हमारी राय में यही सही दृष्टिकोण है।

अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील ने इस संबंध में हमें बॉम्बे उच्च न्यायालय के दो निर्णित निर्णय संदर्भित किये हैं। पहला मामला है यशवंता बनाम अंतु, जहां विधवा ने अपनी बेटी के साथ मिलकर जिसके पास तत्काल उत्तराधिकारी है, एक अजनबी के पक्ष में पूरी संपत्ति को उपहार देने का एक विलेख निष्पादित किया, जो एक पूर्व-मृत बेटी का पति था। यह माना गया कि लेनदेन समर्पण के सिद्धांत के आधार पर वैध था। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि यह मामला सीधे नोबोकिशोर के मामले में प्रतिपादित सिद्धांत के दायरे में आता है, और दो भौतिक तथ्य हैं जो इसे हमारे सामने वाले मामले से अलग करते हैं।

पहले स्थान पर प्रत्यावर्ती ने विधवा के साथ मिलकर एक अजनबी के पक्ष में हस्तांतरण किया और दूसरे, अजनबी को हस्तांतरण पूरी संपत्ति का था। ऐसे लेन-देन को समर्पण का वैध कार्य मानने में कोई कठिनाई

नहीं हो सकती।

एक अन्य मामले में जो बाला धोंडी बनाम बया आईएलआर 60 बॉम्बे 211 में उल्लेख किया गया है, के तथ्य कुछ हद तक वर्तमान मामले के समान हैं, लेकिन वास्तविक निर्णय अपीलकर्ताओं की सहायता नहीं करता है। वहां एक हिंदू विधवा ने अपने पति की पूरी संपत्ति अपनी बेटी और उसके पति के पक्ष में संयुक्त रूप से दान कर दी, उस समय बेटी अगली उत्तराधिकारी थी। निचली अपीलीय अदालत ने माना कि उपहार एक वैध समर्पण था, लेकिन अपील पर उच्च न्यायालय ने इस फैसले को पलट दिया और यह माना गया कि लेनदेन कानून में वैध नहीं था क्योंकि यह केवल बेटी के पक्ष में उपहार नहीं था बल्कि अपने दामाद के पक्ष में भी जिसे बेटी के साथ संयुक्त रूप से लेना था। आगे यह माना गया कि बेटी नाबालिग होने के कारण अपने पति के पक्ष में उपहार के लिए सहमति देने में सक्षम नहीं थी। यह सच है कि वर्तमान मामले में अल्पमत का कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन निर्णय निश्चित रूप से उस बिंदु पर कोई निर्णय नहीं है जिस पर उन्हें निर्णय लिया जाना है। हमारी राय में, दस्तावेज (प्रदर्शन पी-6) के कानूनी प्रभाव के संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण सही है और इसलिए श्री राजा अय्यर द्वारा उठाया गया पहला तर्क विफल होना चाहिए।

अब हम दूसरे बिंदु पर आते हैं जो अन्तःकालीन लाभ के सवाल से

संबंधित है। इस शीर्षक के तहत श्री अय्यर का मुख्य तर्क यह है कि चूँकि विधवा द्वारा किया गया अंतरण शून्य नहीं है, बल्कि केवल शून्यकरणीय है और प्रत्यावर्तक मुकदमा दायर करके इससे बच सकता है, इसलिए उस तारीख से पहले अन्तरिति व्यक्ति के कब्जे को गैरकानूनी नहीं माना जा सकता है और इसके परिणामस्वरूप मुकदमा शुरू होने से पहले की अवधि के लिए किसी भी आंतरिक लाभ की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए थी। उनके तर्क का दूसरा पहलू यह है कि अनुसूची की संपत्ति संख्या 1 के संबंध में प्रतिवादी 2 और 3 के खिलाफ केवल एक सशर्त डिक्री पारित की गई थी और जब तक वादी द्वारा अदालत में आवश्यक राशि जमा करने की शर्त पूरी नहीं की जाती, तब तक वादी को कब्जा लेने का अधिकार नहीं मिलता है और परिणामस्वरूप उन्हें किसी भी प्रकार का कोई लाभ नहीं दिया जा सकता है। इस तर्क के समर्थन में बनवारीलाल बनाम महेश आईएलआर 41 इलाहबाद 63 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले पर विश्वास जताया गया।

जहां तक विवाद के पहले पहलू का संबंध है, यह बताया जा सकता है कि बिजोया गोपाल बनाम कृष्णा महिषी में न्यायिक समिति के निर्णय से पहले एक हिंदू विधवा की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति को वापस लेने वाले की तुलना में अलग करने वाले की कानूनी स्थिति के बारे में कुछ गलत धारणा थी। न्यायिक समिति द्वारा पहले के एक मामले में यह माना गया था कि विधवा द्वारा किया गया अंतरण शून्य नहीं बल्कि

शून्यकरणीय है और प्रत्यावर्तक इस पर सहमति दे सकता है और इसे वैध मान सकता है। यह विधवा की मृत्यु पर बिल्कुल समाप्त नहीं हुआ। इस निर्णय के आधार पर इसे बिजोया गोपाल बनाम कृष्णा महिषी में कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया था कि एक प्रत्यावर्तक के लिए विधवा की संपत्ति पर कब्जा हासिल करने से पहले अंतरण को अलग रखना आवश्यक था और इस तरह के अंतरण को अलग करने के लिए मुकदमे की सीमा की अवधि भारतीय परिसीमा अधिनियम के अनुच्छेद 91 द्वारा निर्धारित की गई थी। प्रिवी काउंसिल को अपील किये जाने पर माननीय द्वारा यह उल्लेखित किया गया कि यह दृष्टिकोण एक गलत धारणा पर आधारित था और उन्होंने बताया कि किस अर्थ में एक हिंदू विधवा द्वारा अंतरण शून्य नहीं बल्कि रद्द करने योग्य था। यह कहा गया था कि एक हिंदू विधवा द्वारा किया गया अंतरण विधवा के मरते ही पूरी तरह से शून्य नहीं हो जाता क्योंकि, यदि ऐसा होता तो इसे प्रत्यावर्ती द्वारा बिल्कुल भी अनुमोदित नहीं किया जा सकता था। अंतरण हालांकि पूरी तरह से शून्य नहीं है, प्रत्यावर्ती उत्तराधिकारी के चुनाव में प्रथम दृष्टया रद्द करने योग्य है। यदि वह उचित समझता है तो वह इसकी पुष्टि कर सकता है या वह अपनी खुशी से किसी भी अदालत के हस्तक्षेप के बिना इसे अमान्य मान सकता है और वह संपत्ति पर कब्जा वापस पाने के लिए कार्रवाई शुरू करके बाद में ऐसा करने के लिए अपना चुनाव दिखा सकता है। वास्तव में प्रत्यावर्ती उत्तराधिकारी के कार्रवाई के अधिकार की

पूर्व शर्त के रूप में अदालत के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे वह रद्द कर दे। एक विधवा द्वारा अलग की गई संपत्ति पर कब्जा वापस पाने के लिए प्रत्यावर्तक का मुकदमा अच्छी तरह से तय हो चुका है, परिसीमा अधिनियम के अनुच्छेद 141 द्वारा शासित होता है और यह आवश्यक नहीं है कि कब्जे के लिए किसी भी डिक्री से पहले हस्तांतरण को रद्द कर दिया जाए। बस इतना आवश्यक है कि विधवा की मृत्यु के 12 वर्ष के भीतर प्रत्यावर्तीकर्ता को कब्जे के लिए मुकदमा दायर करना चाहिए और ऐसे मुकदमे में पारित डिक्री इस आधार पर होनी चाहिए कि विधवा की मृत्यु के बाद से हस्तांतरिती का कब्जा गैरकानूनी था। यह स्थिति होने के कारण, हम सोचते हैं कि विधवा की मृत्यु की तारीख से प्रत्यावर्ती को अन्तरिति के विरुद्ध अन्तःकालीन लाभ की अनुमति देना बिल्कुल उचित है। विधि का ऐसा कोई नियम नहीं है कि ऐसे मामले में किसी भी प्रकार के अंतःकालीन लाभ की अनुमति नहीं दी जा सकती है। जहां अंतरण को बिल्कुल शून्य के रूप में वर्णित नहीं किया गया हो। भगवत दयाल बनाम देवीदयाल और सतगुर प्रसाद बनाम हरनारायण सिंह एलआर 59 आई.ए. 147 में न्यायिक समिति के निर्णयों को उदाहरण के रूप में उद्धृत किया जा सकता है, जहां ऐसे लेनदेन जो शून्यकरणीय हो, में अन्तःकालीन लाभ की अनुमति दी गई थी। हम आगे सोचते हैं कि एक विधवा के संक्रामणग्राही और मिताक्षरा पिता की संयुक्त संपत्ति के अंतरिती के बीच अंतर है। मिताक्षरा पिता का पुत्र भारतीय सीमा अधिनियम के अनुच्छेद

125 में निर्धारित अवधि के भीतर पिता द्वारा किए गए अंतरण को रद्द करने के लिए बाध्य है और अंतरण को रद्द किए जाने पर ही वह संपत्ति पर कब्जा पाने का हकदार है। हमारी राय में उच्च न्यायालय बनवारीलाल बनाम महेश में पारित निर्णय जो कि मिताक्षरा विधि के तहत पिता के अंतरिति के खिलाफ पुत्र द्वारा संस्थित वाद के संबंध में था, इस वर्तमान वाद के तथ्यों पर लागू नहीं होता है। यह सत्य है कि प्रतिवादी 2 और 3 के संबंध में डिक्री एक सशर्त डिक्री है और वादी तब तक कब्जा वापस नहीं पा सकता जब तक कि वह उस सीमा तक एक निश्चित राशि का भुगतान नहीं करता है, जिस सीमा तक विधवा की संपत्ति को लाभ हुआ माना गया है। लेकिन उच्च न्यायालय ने इस राशि पर बहुत ही उचित तरीके से संक्रामणग्राही व्यक्ति को उचित हित की अनुमति दी गई, जबकि बाद वाले को अंतःकालीन लाभ के लिए उत्तरदायी बनाया गया।

नतीजा यह है, कि हमारी राय में इन दोनों बिंदुओं में से किसी पर भी उच्च न्यायालय के फैसले पर आपत्ति नहीं जताई जा सकती है और इसलिए अपील विफल हो जाती है और जुर्माने के साथ खारिज कर दी जाती है।

अपील खारिज।

अपीलकर्ताओं के प्रतिनिधि: एम 0 एस 0 के0 अयंगर।

प्रत्यर्थीगण के प्रतिनिधि: एम 0 एस 0 के0 शास्त्री।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी देवेन्द्र सिंह पंवार,(आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।